

**न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद**  
(अरुण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)  
माता-पिता भरण पोषण अपील संख्या: 01/2025  
दायर दिनांक: 03.02.2025  
निर्णय दिनांक 13.02.2026

-:अनवान:-

बबली देवी पत्नि स्वर्गीय दिनेश जी जाति कुम्हार निवासी कुम्हारवाडा  
नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद - अपीलाण्ट

बनाम

कंकुबाई पत्नि घनश्याम जी जाति कुम्हार निवासी सुखाडिया नगर नाथद्वारा  
हाल महावीर कॉम्पलेक्स के पास, बस स्टेण्ड नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा  
जिला राजसमन्द - रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 06.12.2024 द्वारा माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
नाथद्वारा, बअनवान कंकुबाई बनाम सुभाष व अन्य प्रकरण संख्या 04/2022  
से व्यथित होकर

उपस्थित:-

- 1- श्री सुखलाल बैरवा, अधिवक्ता अपीलाण्ट
- 2- श्री विक्रम कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा के प्रकरण संख्या 04/2022 निर्णय दिनांक 06.12.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। रेस्पोंडेण्ट ने अपने जवाबदावे में समस्त सम्पत्तियों को पुश्तैनी व मौरूसी बताया है, जो घनश्याम जी जो अपने बाप दादाओं से प्राप्त हुई है। मौरूसी व पुश्तैनी से अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के जेठ जी सुभाष जी कैलाश जी सभी को उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है व सभी का बराबर हक व अधिकार है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा रहने के लिए इजाजत देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरी अंदाज कर अपीलाण्ट को बेदखल करने में भारी भूल की है। रेस्पोंडेण्ट वृद्ध महिला होकर वह अपनी तल्लाकशुदा पुत्री रेखा के असम्यक प्रभाव व दबाव में आकर यह प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट व विपक्षीगण के समक्ष प्रस्तुत किया है। रेस्पोंडेण्ट की पुत्री, अपीलाण्ट व उनके दोनों जेठ जी घनश्याम जी की समस्त जायदाद से बेदखल करने के आशय से यह झूठा प्रार्थना पत्र गलत



*(Handwritten signature)*

तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर उक्त आदेश पारित किया जो अवैध है। अपीलान्ट के पति दिनेश का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट के तीन छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। अपीलान्ट अपने स्वयं का व अपने बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके करती है। अपीलान्ट कुम्हारवाड़ा में स्थित जायदाद पर बने एक कमरे में वर्तमान में निवास कर रही है। यदि अपीलान्ट को उक्त कमरे से बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्ट व उसके बच्चे बच्ची रहने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी एवं दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो जायेगे। रेस्पोजेण्ट को 1500/- रुपये वृद्धावस्था पेंशन भी प्राप्त होती है फिर रेस्पोजेण्ट कुम्हार वाड़ा स्थित मकान के आगे सुखी लकड़ियों का स्टोक कर बेचने का काम करती है जिससे उसे आसानी से कमाई हो जाती है। केवल मात्र रेस्पोजेण्ट द्वारा उसकी पुत्री रेखा के बहकावे में आकर अपीलान्ट के विरुद्ध केवल मात्र हैरान परेशान करने के लिए यह कार्यवाही कराई है ताकि अपीलान्ट हैरान परेशान होकर अन्यत्र नाते चली जावे एवं जायदाद में अपीलान्ट का हिस्सा है उसे प्राप्त हो सके। पक्षकारान के मध्य विवाद उत्तराधिकार से संबंधित होकर मामला सिविल प्रकृति का है, फिर भी रेस्पोजेण्ट अपीलान्ट के साथ रहे तो अपीलान्ट उसका भरण पोषण करने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोजेण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम कुमावत ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। रेस्पोजेण्ट ने अपने जवाबदावे में समस्त सम्पत्तियों को पुश्तैनी व मौरूसी बताया है, जो अपने बाप दादाओं से प्राप्त हुई है। मौरूसी व पुश्तैनी से अपीलान्ट व अपीलान्ट के जेठ जी सुभाष जी कैलाश जी सभी को उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है व सभी का बराबर हक व अधिकार है। रेस्पोजेण्ट द्वारा रहने के लिए इजाजत देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरी अंदाज कर अपीलान्ट को बेदखल करने में भारी भूल की है। रेस्पोजेण्ट वृद्ध महिला होकर वह अपनी तल्लाकशुदा पुत्री रेखा के असम्यक प्रभाव व दबाव में



*deh*

आकर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व विपक्षीगण के समक्ष प्रस्तुत किया है। रेस्पोजेण्ट की पुत्री, अपीलांट व उनके दोनों जेठ जी घनश्याम जी की समस्त जायदाद से बेदखल करने के आशय से यह झूठा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर उक्त आदेश पारित किया जो अवैध है। अपीलाण्ट के पति दिनेश का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्ट के तीन छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। अपीलांट अपने स्वयं का व अपने बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके करती है। अपीलांट कुम्हारवाडा में स्थित जायदाद पर बने एक कमरे में वर्तमान में निवास कर रही है। यदि अपीलांट को उक्त कमरे से बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट व उसके बच्चे बच्ची रहने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी एवं दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो जायेंगे। रेस्पोजेण्ट को 1500/- रुपये वृद्धावस्था पेंशन भी प्राप्त होती है फिर रेस्पोजेण्ट कुम्हार वाडा स्थित मकान के आगे सुखी लकड़ियों का स्टोक कर बेचने का काम करती है जिससे उसे आसानी से कमाई हो जाती है। केवल मात्र रेस्पोजेण्ट द्वारा उसकी पुत्री रेखा के बहकावे में आकर अपीलांट के विरुद्ध केवल मात्र हैरान परेशान करने के लिए यह कार्यवाही कराई है ताकि अपीलांट हैरान परेशान होकर अन्यत्र नाते चली जावे एवं जायदाद में अपीलांट का हिस्सा है उसे प्राप्त हो सके। पक्षकारान के मध्य विवाद उत्तराधिकार से संबंधित होकर मामला सिविल प्रकृति का है, फिर भी रेस्पोजेण्ट अपीलांट के साथ रहे तो अपीलांट उसका भरण पोषण करने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर समुचित न्यायिक प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। रेस्पोजेण्ट एक वृद्ध महिला है, रेस्पोजेण्ट के संताने होने के बावजूद अपीलान्ट द्वारा रेस्पोजेण्ट वृद्ध महिला को बेसहारा छोड़ रखा है जिसके कारण उसे अन्यत्र किराये के मकान में रहना पड़ रहा है। नाथद्वारा में तीन-तीन मकान होने के बावजूद रेस्पोजेण्ट को निराश्रित होकर निवास करना पड़ रहा है तथा संतानों द्वारा इनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है और सुखाड़िया नगर वाला मकान रेस्पोजेण्ट का स्व0 अर्जित मकान है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से उक्त अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उक्त संपत्ति मौरूसी व पुश्तैनी से अपीलांट व अपीलांट के जेठ जी सुभाष जी कैलाश जी सभी को उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है व सभी का



*deh*

बराबर हक व अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अंदाज कर अपीलान्त को बेदखल करने में भारी भूल की है। अपीलान्त के पति दिनेश का स्वर्गवास हो चुका है और अपीलान्त के तीन छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। पक्षकारान के मध्य विवाद उत्तराधिकार से संबंधित होकर मामला सिविल प्रकृति का है, फिर भी रेस्पोंडेंट अपीलान्त के साथ रहे तो अपीलान्त उसका भरण पोषण करने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

उक्त संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि विधवा पुत्रवधू का अधिकार यह न्यायालय स्वीकार करता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी की विधवा पुत्रवधू है। साथ ही मानवीय जीवन का अधिकार भारत के संविधान और मानवीय गरिमा के आलोक में, अपीलार्थी को भी सम्मानपूर्वक मानव जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि आवास का अधिकार के संबंध में देखे तो जीवन जीने के अधिकार के तहत अपीलार्थी को कुम्हारवाड़ा स्थित मकान से निष्कासित (बाहर) नहीं किया जा सकता है।

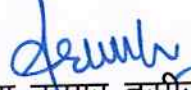
अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### :: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित रखने हेतु यह आदेश दिया जाता है कि उसे कुम्हारवाड़ा स्थित मकान से निष्कासित (बाहर) नहीं किया जाए। एवं इस प्रकरण के शेष निर्णय और भरण-पोषण सम्बन्धी शर्तें पूर्व में न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उखण्ड अधिकारी नाथद्वारा द्वारा पारित प्रकरण संख्या 04/2022 के आदेश के अनुरूप ही रहेंगी।

  
(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 13.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

